



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1982/ज्येष्ठ 8, 1904

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1982/JYAISTHA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(विधि कार्य विभाग)

(Department of Legal Affairs)

सूचना

NOTICE

नई दिल्ली, 12 मई, 1982

New Delhi, the 12th May, 1982

क्रा० आ० 1894.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री नारायण चन्द्र डे, सं० 128/सी, नारिकेलडंगा रेलवे कॉलोनी, कलकत्ता-700011 ने उक्त प्राधिकारी की उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता और 24-परगनाज में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

S.O. 1894.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Narayan Chandra De, Advocate No. 128/C, Narikeldanga Railway Colony, Calcutta-700011 for appointment as a Notary to practise in Calcutta & 24-Parganas.

2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[सं० फा० 5 (38)/82-न्या०]

[No. F. 5(38)/82-Judl.]

के० सी० डी० गंगवानी, सक्षम प्राधिकारी

K. C. D. GANGWANI, Competent Authority

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1982

आयकर

का० आ० 1895.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "सलेम डायोसेस सोसायटी" को निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1982-83 तक की अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4569/का० सं० 197/200/81-आ० क० (ए1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th April, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 1895.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Salem Diocese Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1982-83.

[No. 4569/F. No. 197/200/81-IT(AI)]

(आयकर)

का० आ० 1896.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "द जुमा मसजिद आफ मुम्बई ट्रस्ट" का निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक की अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4567/का० सं० 197/159/81-आ० क० (ए1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1896.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Juma Masjid of Bombay Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1978-79 to 1981-82.

[No. 4567/F. No. 197/159/81-IT(AI)]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1982

(आयकर)

का० आ० 1897.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "टूटीकोरिन डायोसेस एसोसिएशन" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक की अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4584/का० सं० 197/69/80-आ० क० (ए1)]

मिलाप जैन, प्रवर सचिव

New Delhi, the 20th April, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 1897.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Tuticorin Diocesan Association" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1978-79 to 1981-82.

[No. 4584/F. No. 197/69/80-IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy.

आयकर

नई दिल्ली, 4 मई 1982

स्टाम्प

का० आ० 1898.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्स कम्पनी लि० को, मात्र पेंसालीम हुजूर रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क को अदा करने की अनुमति देती है, जो उक्त कम्पनी द्वारा साठ लाख रुपये के अंकित मूल्य के ऋण-पत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बंध-पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभावी है।

[सं० 20/82-स्टाम्प/का० सं० 33/13/82-वि०-क०]

भगवान दाम, प्रवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th May, 1982

STAMPS

S.O. 1898.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Ahmedabad Shri Ramakrishna Mills Co. Ltd., to pay consolidated stamp duty of fortyfive thousands rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of sixty lakhs of rupees to be issued by the said company.

[No. 20/82-Stamp/F. No. 33/13/82-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 1982

का० आ० 1899.—केन्द्रीय सरकार, सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 के नियम 11 के उप-नियम (1) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री फौजा सिंह गिल को 12 मई, 1982 से एक वर्ष की अवधि के लिए, सम्पत्ति सम्पत्ति अपील अधिकरण का अध्यक्ष पुनः नियुक्त करती है।

[का० सं० 22/3/82-प्रशा० 1-ए (सी)]

सी० एल० खन्ना, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1982

S.O. 1899.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Clause (a) of Sub-rule (1) of rule 11 of the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, the Central Government hereby re-appoints Shri Justice Fauja Singh Gill, retired Judge of the Delhi High Court as Chairman, Appellate Tribunal for Forfeited Property, for a further period of one year with effect from the 12th May, 1982.

[F. No. 22/3/82-AD. I-A(C)]

C.L. KHANNA, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1982

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का० आ० 1900 :—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का संख्याक 54) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय राजस्व सेवा (प्रायकर) के अधिकारी, श्री एम० एस० उन्नीनायर को, 22 अप्रैल, 1982 के दोपहर बाद से अगला भावेश होने तक केन्द्रीय अध्यक्ष-कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[का० सं० ए-19011/59/82-प्रशा (1)]

जी० ए० मेहरा, अधर सचिव

New Delhi, the 29th April, 1982

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 1900.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri M. S. Unninar, an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax), as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the afternoon of the 22nd April, 1982 and until further orders.

[F. No. A-19011/59/82-AD.I]

G.S. MEHRA, Under Secy

आर्थिक कार्य विभाग

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

का० आ० 1901 :—यतः राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1880 के खण्ड 3 के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रान्थ बैंक के निदेशक मण्डल का गठन किया जाना है;

अतः अब उक्त स्कीम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ग्रान्थ बैंक के निदेशक मण्डल का 17 अप्रैल, 1982 में गठन करती है; और

(क) निम्नलिखित सारणीक के कालम (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को क्रमशः उक्त सारणीक के कालम (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए यथा स्थिति प्रबन्ध निदेशक प्रथवा निदेशक; और

(ख) निम्नलिखित सारणी ख में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त बैंक का निदेशक नियुक्त करती है :—

सारणी क

1	2
1. श्री के० गोपालकृष्ण मूर्ति प्रबन्ध निदेशक- धारा 3 की उपधारा (क) के अनुसरण में।	17 अप्रैल, 1982 से शुरू होकर 23 सितम्बर, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए।

निदेशक

2. श्री यू० जी० राव 23-15-48, जी० एम० राजू रोड सत्यनारायणपुरम विजयवाड़ा- 520011 (आंध्र प्रदेश) —उक्त बैंक के जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए—धारा 3 की उपधारा (घ) के अनुसरण में
3. श्री दूरेश्वर कुमार मिश्रा, राम धावा, डाकघर जम्हावर, जिला औरंगाबाद, डाकघर जम्हावर, जिला औरंगाबाद, डाकघर जम्हावर, जिला औरंगाबाद 17 अप्रैल 1982 से शुरू होकर 16 अप्रैल, 1985 को

1

2

बाद (बिहार)—किमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

समाप्त होने वाली अवधि के लिए।

—धारा 3 की उपधारा (इ) के अनुसरण में।

4. कुमारी रेनाना माबवाला, सचिव सेल्फ एम्प्लॉएड वीमन्स एसोसिएशन (एन० ई० डब्ल्यू० ए०) सेवा रिसोर्स सेंटर, भद्रा, महमदाबाद- 380001 गुजरात)

-तदेव-

—शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए—धारा 3 की उपधारा (इ०) के अनुसरण में।

5. श्री जी० नटराजन चार्टर्ड एकाउंटेंट 283, मोन्टेस रोड, मद्रास 600018 —(तमिलनाडु) धारा 3 की उपधारा (च) के अनुसरण में।

-तदेव-

6. श्री के० सांबा शिवा राय, अभियंता 8-3-320/ए/1 येल्ला रेडी गुडा ह्वेराबाद- 500873 (आन्ध्र प्रदेश) —धारा 3 की उपधारा (च) के अनुसरण में।

-तदेव-

7. श्री खुशी राम, डी- 163, मानमरोवर गाहंन, नई दिल्ली-110015 —धारा 3 की उपधारा (च) के अनुसरण में।

-तदेव-

8. श्री बी० के० महुंती, सामाजिक कार्यकर्ता, डाकघर बीरमित्तपुर, जिला सुंदरगढ़- 770033 (उड़ीसा) —धारा 3 की उपधारा (च) के अनुसरण में।

-तदेव-

9. श्री मुनील जाखड़ 20, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011 17 अप्रैल, 1982 से शुरू होकर 16 अप्रैल 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए।

सारणी ख

1. श्री विनेश चन्द्र, निदेशक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली-110001 —धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में।

[सं० एफ० 9/39/81 सी० प्रो०-1]

Department of Economic Affairs
Banking Division
New Delhi, 17th April, 1982

S.O. 1901 :—Whereas, a Board of Directors of Andhra Bank, a nationalised bank, is to be constituted under clause 3 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

Now, Therefore, in pursuance of the said Scheme, the Central Government hereby constitutes the Board of Directors of Andhra Bank with effect from 17th April, 1982 and appoints—

- (a) the persons specified in column (1) of Table A below as the Managing Director or Directors, as the case may be, of the said Bank for the respective period specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table; and

(b) the person specified in Table B below as the Director of the said Bank :—

TABLE A

1	2
1. Shri K. Gopalakrishna Murthy Managing Director in pursuance of sub-clause (a) of clause 3.	For the period commencing on 17th April, 1982 and ending with 23rd September, 1984.
DIRECTORS	
2. Shri U. Joga Rao, 23-15-48, G.S. Raju Road, Satyanarayana-puram, Vijayawada-520011, (Andhra Pradesh)	For the period commencing on 17th April, 1982 and ending with 16th April, 1985.
representing the interests of depositors of the said bank—in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.	
3. Shri Dudeswar Kumar Misra, Vill. Dhawa, P.O. Jamhour, Distt. Aurangabad (Bihar)	For the period commencing on 17th April, 1982 and ending with 16th April, 1985.
representing the interests of farmers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.	
4. Miss Renana Jhabvala, Secretary, Self Employed Women's Association (SEWA) Sewa Reception Centre, Bhadra, Ahmedabad-380001 (Gujarat)	-do-
representing the interests of artisans in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.	
5. Shri G. Natarajan, Chartered Accountant, 283 Mowbrays Road, Madras-600018 (Tamil Nadu)	-do-
in pursuance of sub-clause (f) of Clause 3.	
6. Shri K. Samba Siva Rao, Engineer, 8-3-320/A/1, Yella Reddi Guda, Hyderabad- 500873 (Andhra Pradesh)	-do-
in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.	
7. Shri Khushi Ram, D-163, Mansarovar Garden, New Delhi-110015.	-do-
in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.	
8. Shri B.K. Mihinti, Social Worker, P.O. Birmitrapur, Distt. Sundergarh-770033 (Orissa)	-do-
in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.	

1	2
9. Shri Sunil Jakhar, 20, Akbar Road, New Delhi-110011.	For the period commencing on 17th April, 1982 and ending with 16th April, 1985.
in pursuance of sub-clause (f) of clause 3	

TABLE B

1. Shri Dinesh Chandra, Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.

in pursuance of sub-clause (h) of clause 3.

[No. F. 9/39/81-B.O.-I(1)]

नई दिल्ली, 6 मई, 1982

क्रा.आ. 1902—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 के खंड 3 के उपखंड (ड) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा नीचे की सारणी के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक के सामने उसी सारणी के कालम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों के स्थान पर सारणी के कालम (1) में दिये गये राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी		
(1)	(2)	(3)
1. आन्ध्र बैंक	श्री प्रो.पी.तनेजा, प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिवालय मार्ग, हैदराबाद-500004	श्री बी.एम. मोहरीर
2. न्यू बैंक ऑफ इंडिया	श्री एम.के. वेसाई, श्री टी.के. वेलायुधम उा मुख्य अधिकारी, बैंकिंग परिषालन तथा विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक कफ परेड, बम्बई-400005	

[संक्रा.एफ. 9/6/82-बो.प्रो.1]

ब.वा.मीरचन्दानी, उप सचिव

New Delhi, 6th May, 1982

S.O. 1902.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE		
(1)	(2)	(3)
1. Andhra Bank	Shri O.P. Taneja Manager, Reserve Bank of India, Secretariat Road, Hyderabad-500004	Shri V.S. Moharir
2. New Bank of India	Shri M.K. Desai Deputy Chief Officer, Department of Banking Operations & Development, Reserve Bank of India, Cuffe Parade, Bombay-400005.	Shri T.K. Velayudham

[No. F.-9/6/82-BO-I]

C.W. MIRCHANDANI, Dy Secy.

नई दिल्ली, 12 मई, 1982

कांशा० 1903.—बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के फार्म "क" के साथ संलग्न टिप्पणी (च) के उपबन्ध, 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार तैयार किये गये यूनाइटेड कर्माग्नयल बैंक के तुलन पत्रों पर, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जब उक्त फार्म की संपत्ति तथा परिपक्व शीर्ष की सब 4 के उपशीर्ष (ii), (iii), (iv) और (v) के समाने श्रेणियों के फार्म में दिखाया गया मूल्य उस उपशीर्ष के अन्तर्गत किये गये विवेकों का बाजार मूल्य से बढ़ जायेगा। उस उपशीर्ष के अन्तर्गत किये गये विवेकों का बाजार मूल्य कोष्ठकों के अन्तर अलग से दिखाया गया है।

[संख्या 15/2/82-बी०मी०III]

एन०डी० बत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th May, 1982

S.O. 1903.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the United Commercial Bank in respect of its balance sheet as at the 31st December 1981 which, when the value shown in the inner column against any of the sub-heads (ii), (iii), (iv) and (v) of the item 4 of the Property and Assets side of the said Form, exceeds the market value of the investments under that sub-head, shows separately within brackets the market value of the investments under the sub-head.

[No. 15/2/82-B.O. III]

N. D. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मई, 1982

कांशा० 1904.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारी-वृद्ध ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिभूजित करती है :-

- (1) भारतीय रिजर्व बैंक, पटना कार्यालय।
- (2) भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर कार्यालय।

[संख्या ई-11017/2/82-हिन्दी]

बिनोद प्रकाश सहनी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 3rd May, 1982

S.O. 1904.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Reserve Bank of India, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

1. Patna Office of Reserve Bank of India.
2. Jaipur Office of Reserve Bank of India.

[No. E-11017/2/82-Hindi]
V. P. SAWHNEY, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1982

कांशा० 1905.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तारीख 2-10-1975 के उस

समय के बैंकिंग विभाग के एस०मी० 571(ई०) संख्या एफ० 4-15/75 एस०मी०आई०) अर्थात् भारत सरकार की उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है कि "मुरादाबाद जिले" शब्दों के स्थान पर "मुरादाबाद तथा रामपुर जिले" को प्रतिस्थापित किया जाए।

[संख्या एफ० 1-13/81-आर०आर०बी०]

विनेश चन्द्र, निदेशक

New Delhi, the 21st April, 1982

S.O. 1905.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (3) of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the then Department of Banking S.O. 571(E) (No. F. 4-15/75-AC), dated the 2-10-1975 namely in the said notification for the words "district of Moradabad", the words "districts of Moradabad and Rampur" shall be substituted.

[No. F.1-13/81-RRB]

DINESH CHANDRA, Director

नयी दिल्ली, 13 मई, 1982

कांशा० 1906.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंटों की निम्नलिखित फर्मों को वर्ष 1981-82 के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा परीक्षकों के रूप में पुनर्नियुक्त करती है, अर्थात्:—

1. मैसर्स बाटलीबोई एण्ड पुरोहित, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नेशनल इन्श्योरेंस बिल्डिंग, 204, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई-400001
2. मैसर्स पी०के० चौपड़ा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, एन०-34, कनाउट सर्कस, नयी दिल्ली।
3. मैसर्स लवलाक एण्ड लोव्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नं०-4, लॉयन्स रेंज, कलकत्ता-700001
4. मैसर्स डी० रंगास्वामी एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 1/142, माउंट रोड, मद्रास-600001

[संख्या 1(6)/82-नेब्रा]

एन० बालासुब्रमण्यम, उप-सचिव

New Delhi, the 13th May, 1982

S.O. 1906.—In exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby reappoint the following firms of Chartered Accountants as Auditors of the Reserve Bank of India for the year 1981-82, namely:—

1. M/s. Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, Dr. Dadabhoy Naroji Road, Bombay 400001.
2. M/s. P. K. Chopra & Co., Chartered Accountants, N-84, Connaught Circus, New Delhi.
3. M/s. Lovelock & Lewes, Chartered Accountants, No. 4, Lyons Range, Calcutta-700001.
4. M/s. D. Rangaswamy & Co., Chartered Accountants, 1/142, Mount Road, Madras-600001.

[No. 1(6)82/Accts.]

N. BALASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य निर्यात-आयात का कार्यालय

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

निरस्त-आवेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1982

का० आ० 1907.—मैमर्न जैन इन्टरप्राइजेज, 95 जी.टी. रोड, गझियाबाद को एक आयात लाइसेंस सं० पी०/एस०/1933025/सी०/XX/80/डी०/81 दि० 3-8-81 बाबते 4,71,272 रु० अप्रैल-मार्च-82 की आयात नीति के अर्पण-काल 5 में लिखित अनुमति सूची के आयात हेतु दिया गया था।

आवेदक फर्म ने आयात-निर्यात की कार्यविधि-पुस्तिका 1981-82 के पैरा 352 के अन्तर्गत एक अपथ-नमूना प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि अप्रैल-मार्च-82 की आयात-नीति के अन्तर्गत जारी लाइसेंस सं० पी०/एस०/1933025 दि० 3-8-81 बाबते 4,71,272 रु० की कस्टम शुल्क कापी बम्बई कस्टम पर पंजीकृत होने तथा 1,88,064 रु० तक इस्तेमाल होने के पश्चात् खो गई है।

मैं सन्तुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल कस्टम हेतु कापी खो गई है।

अतः आयात-आयात निर्यात आदेश 1955 दि० 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9(CC) में प्रदत्त अधिकारों, का प्रयोग करने हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस पी०/एस०/1933025 दि० 3-8-81 बाबते शेष राशि 2,83,208 रु० की मूल कस्टम कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूँ।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि-पुस्तिका 1981-82 के पैरा 351-354 के अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की कस्टम कापी की अनुमिति (डुप्लिकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[सं० यू०पी०/जे०-7/ए०एम०-82/ए०यू०-1/डी०एल०ए०]

(कु०) भाषा दास गुप्ता,

उप-मुख्य निर्यात-आयात-निर्यात

हूने संयुक्त मुख्य निर्यात-आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

(Central Licensing Area)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 30th March, 1982

S.O. 1907.—M/s. Jain Enterprises, 95 G.T. Road, Ghaziabad was granted import licence No. P/S/1933025/C/XX/80/D/81 dated 3-8-81 for Rs. 4,71,272 for import of items as permissible under Appendix-5 of AM-82 Policy Book.

The applicant has filed an affidavit as required under Para 352 of Hand Book of Import Export Procedure 1981-82 wherein they have stated that Custom Purposes copy of licence No. P/S/1933025 dated 3-8-81 for Rs. 4,71,272 for AM-82 period has been lost/misplaced having been registered with Bombay Customs and utilised to the extent of Rs. 1,88,064.

I am satisfied that the original Custom purposes copy of the said licence has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under sub-clause 9(cc) in the Import Trade Control Order 1955 dated 7-12-55 as amended upto date the said original custom purpose copy of licence No. P/S/1933025 dated 3-8-81 for the balance amount of Rs. 2,83,208 is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate Custom purposes copy of Import licence No. P/S/1933025 dated 3-8-81 for the balance amount in accordance with the provision of Paras 351 to 354 of Hand Book of Import Export procedure 1981-82.

[File No. UP/J-7/AM-82/AU-J/CLA]

(MISS) MAYA DASS GUPTA,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports
for Jt. Chief Controller of Imports and Exports**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय**

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 1982

का० आ० 1908.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पार्श्वपदाहन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3134 तारीख 20/8/79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को वाह्य लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अहित करने का अपना आदेश घोषित कर दिया था।

और यतः मन्त्र प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अहित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अहित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के पश्चात् और प्राकृतिक गैस प्रयोग में सभी बाधाओं से मुक्त हो, घोषणों के प्रकाशन की इस तारीख की दिवस होगा।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से बकिण कड़ी तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात	जिला : महेशाना	तहसील : कड़ी		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	घार	सेटीयर
1	2	3	4	5
कुन्डाल	434	0	03	75
	435	0	01	70
	431	0	06	45
	438/1	0	05	25

1	2	3	4	5
	446	0	04	80
	459	0	02	20
	460	0	04	05
	456	0	02	00
	455	0	01	70
	454/1	0	02	15
	453	0	02	70
	452	0	02	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	35
	544	0	00	60
	545/1	0	01	50
	545/2	0	02	00
	555	0	01	90
	556	0	01	30
	554	0	02	25
	552/2	0	02	00
	549	0	00	10
	552/1	0	00	85
	550	0	05	00
	592/1	0	00	50
	कान्स	0	01	00
	591/3	0	03	25
	776/1 + 2	0	02	60
	645/1	0	03	00
	646/1	0	00	20
	776/1	0	02	00
	775	0	02	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	85
	777	0	04	85
	778/1	0	01	60
	778/2	0	01	50
	780	0	16	50
	781	0	02	25
	787	0	09	00
	790	0	09	30
	794	0	03	75
	793	0	05	60
	1/बी	0	01	75

[सं० 12016/42/79-प्रोड-II]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER**(Department of Petroleum)**

New Delhi, the 6th May, 1982

S.O. 1908.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum), S.O. No. 3134 dated 20-8-79 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition on Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1952), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE**ROU For CTC Kalol to South Kadi**

State: Gujarat

District: Mehsana

Taluka: Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centaire
KUNDAL	434	0	03	75
	435	0	01	70
	431	0	06	45
	438/1	0	05	25
	446	0	04	80
	459	0	02	20
	460	0	04	05
	456	0	02	00
	455	0	01	70
	454/1	0	02	15
	453	0	02	70
	452	0	02	00
	Cart track	0	00	35
	544	0	00	60
	545/1	0	01	50
	545/2	0	02	00
	555	0	01	90
	556	0	01	30
	554	0	02	25
	552/2	0	02	00
	549	0	00	10
	552/1	0	00	85
	550	0	05	00
	592/1	0	00	50
	Kans	0	01	00
	591/3	0	03	25
	776/1 + 2	0	02	60
	645/1	0	03	00
	646/1	0	00	20
	776/1	0	02	00
	775	0	02	00
	Cart track	0	00	85
	777	0	04	85
	778/1	0	01	60
	778/2	0	01	50
	780	0	16	50
	781	0	02	25
	787	0	09	00
	790	0	09	30
	794	0	03	75
	793	0	05	60
	1/B	0	01	75

[No. 12016/42/79-Prod.-II]

का०आ० 1909.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल-18 से सी० टी० एफ० नवागाम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

पुनः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक, गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति चिनिदिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल -18 से सी०टी०एफ० नवागाम

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : महमदाबाद

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टर	एअरर्	सेंटियर
लाली	781	0	00	63
	783	0	27	85
	798	0	03	30
	797	0	09	15
	796	0	09	60
	795	0	03	75
	794	0	20	63
	803	0	04	96
	804	0	12	00
	811/A+B	0	12	90
	807	0	19	43
	667	0	22	59
	806	0	09	15
	669/A	0	05	81
	664	0	03	65
	670	0	06	04
	661	0	20	75
	658	0	07	68
	657	0	09	90
	652	0	35	40
कार्टेक	0	03	00	
	519	0	50	10
	473	0	06	45
	474	0	15	00
	463/A+B	0	28	05
	461	0	10	

S.O. 1909.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from RAMOL-18 to C.T.F. NAWAGAM in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM RAMOL-18 TO C.T.F. NAWAGAM
STATE : GUJARAT DISTRICT : KAIRA TALUKA ;

MEHMADABAD

VILLAGE	BLOCK NO.	HECTARE	ARE	CENTIARE
LALI	781	0	00	63
	783	0	27	85
	798	0	03	30
	797	0	09	15
	796	0	09	60
	795	0	03	75
	794	0	20	63
	803	0	04	96
	804	0	12	00
	811/A+B	0	12	90
	807	0	19	43
	667	0	22	59
	806	0	09	15
	669/A	0	05	81
	664	0	03	65
	670	0	06	04
	661	0	20	75
	658	0	07	68
	657	0	09	90
	652	0	35	40
	CART TRACK	0	03	00
	519	0	50	10
	473	0	06	45
	474	0	15	00
	463/A+B	0	28	05
	461	0	10	20

[No. 12016/16/82-Prod. II]

का०आ० 1910.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल-18 से सी०टी०एफ० नवागाम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यहाँ कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल-18 से सी० टी० एफ० नवागम

राज्य: गुजरात	जिला: खेडा तालुका: मेहमदाबाद			
गांव	ब्लॉक न०	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
बीडज	कार्ट ट्रैक	0	00	94
	221	0	09	70
	220	0	06	45
	219	0	09	30
	218	0	00	78

[सं० 12016/16/82-प्रो०-I]

S.O. 1910.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from RAMOL-18 to C.T.F. NAWAGAM in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, with in 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM RAMOL-18 TO C.T.F. NAWAGAM
STATE : GUJARAT DISTRICT : KAIRA
TALUKA : MEHMADABAD

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Bldaj	Car Track	0	00	94
	221	0	09	70
	220	0	06	45
	219	0	09	30
	218	0	00	78

[No 12016/16/82-Prod. I]

का० प्रा० 1911—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल-18 से सी० टी०

एफ० नवागम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यहाँ यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यहाँ कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल-18 से सी० टी० एफ० नवागम

राज्य: गुजरात	जिला: खेडा	तालुका: मातार		
गांव	सर्वे न०	हेक्टेयर	एअर ई.	सेन्टीयर
पिंगलज	152	0	11	10
	153	0	20	40

[सं० 12016/15/82-प्रो०-II]

S.O. 1911.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from RAMOL-18 to C.T.F. NAWAGAM in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, with in 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM RAMOL-18 TO C.T.F. NAWAGAM

State: Gujarat	District : Kaira	Taluka : Matar		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Pingalaj	152	0	11	10
	153	0	20	40

[No. 12016/15/82—Prod. II]

का० आ० 1912—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल-18 से सी० टी० एफ० नवागाम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पार्श्वलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पार्श्वलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पार्श्व लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तित्व हो या किसी विशिष्ट व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची 1

रामोल-18 से सी० टी० एफ० नवागाम

राज्य: गुजरात जिला: अहमदाबाद तालुका: वसकोई

गांव	सर्वे न०	हेक्टेयर एअरर्स सेंटीयर
1	2	3 4 5
बारिजा	653	0 00 36
	654	0 06 85
	655	0 11 10
	659	0 11 83
	656	0 01 56
	694	0 01 12
	665	0 05 82
	692+693	0 09 04
	1+2	
	691/1+2	0 07 78
	698	0 98 80
	699	0 08 70
	744	0 03 06
	742	0 16 05
	741	0 14 64
	757/1 से 6	0 03 90
	767/2	0 08 10
	767/1	0 09 98
	766	0 01 12
	934	0 16 20
	773/2	0 00 10
	773/3	0 05 08
	773/1	0 04 50
	905/16	0 09 92
	905/9	0 00 49
	930/1	0 00 95
	905/2	0 09 90
	929	0 16 65
	925/4	0 03 68
	926	0 08 76
	921/1	0 01 56
	991	0 00 03

1	2	3	4	5
	992	0	04	68
	996	0	01	44
	995/2/2	0	03	41
	995/1	0	04	95
	995/2/1	0	04	92
	997	0	00	08
	994	0	06	95
	1128/1+2	0	02	18
	1126	0	07	56
	1127	0	06	27
	1129/4	0	00	86
	1129/2	0	04	95
	1129/1	0	07	22
	1130/1/1	0	00	75
	1125	0	06	46
	1123	0	06	23
	1124	0	00	06
	1122	0	00	05
	1121	0	11	38
	1115	0	13	05
	1117	0	00	03
	1112/1	0	02	16
	1116/2	0	06	30
	1110/6	0	04	06
	1110/5	0	00	14
	1109/2	0	04	65
	1109/1	0	04	80
	1108/1/1	0	09	49
	1089	0	06	90
	1106	0	04	65
	1090	0	02	89
	1105	0	01	53
	1091	0	06	06
	1092/1+2	0	04	50
	1093	0	07	88
	1094	0	10	47
	1097	0	00	68
	1095	0	03	53
	1096	0	08	32
	1055/5	0	10	73
	1591/1+2+3	0	00	13
	1592/1	0	09	95
	1592/2	0	00	24
	1594	0	00	05
	1593/3	0	09	80
	1593/1	0	00	04
	1603	0	34	43
	1607/3	0	01	80
	1607/2	0	09	55
	1659	0	04	35
	1557	0	05	76
	1658	0	08	25
	1710	0	06	11
	1711/1	0	08	03
	1711/3	0	00	12
	1711/4	0	04	59

1	2	3	4	5
	1714/2	0	01	70
	1713/2	0	08	35
	1713/1	0	05	03
	1727	0	07	35
	1726	0	03	15
	1725	0	06	75
	1723/1	0	05	95
	1722/2	0	00	60
	1722/1	0	10	20
	1720	0	03	61
	1749	0	04	36
	1773/3	0	05	70
	1773/1	0	05	64
	1773/2	0	00	06
	1776/1	0	12	13
	1775	0	01	52
	1790	0	03	83
	1778	0	10	88
	1788/2/2	0	03	38
	1779/1	0	08	98
	1787	0	14	92
	1811	0	01	10
	1786	0	00	37
	1812	0	07	58
	1813	0	01	43
	1824	0	40	33
	1815	0	01	22
	1823	0	01	43
	1822	0	03	98
	1821	0	08	03
	1828	0	15	23
	1830	0	07	14
	कार्ट ट्रैक	0	04	16
	1838	0	03	12
	1833	0	22	97
	1832	0	01	44
	कार्ट ट्रैक	0	00	95
	2114	0	06	30
	2113	0	23	30

[सं० 12016/15/82-प्र० I]

S.O. 1912.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from RAMOL-18 to C.T.F. NAWAGAM in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, with in 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also

state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE				
PIPELINE FROM RAMOL 18 TO C.T.F. NAWAGAM				
State: Gujarat		District : Ahmedabad		Maluka: Das-cro
Village	Survey No.	Hectare	Acre	centiare
BAREJA	653	0	00	36
	654	0	06	85
	655	0	11	10
	659	0	11	83
	656	0	01	56
	694	0	01	12
	665	0	05	82
	692+693	0	09	04
	1+2			
	691/1+2	0	07	78
	698	0	08	80
	699	0	08	70
	744	0	03	06
	742	0	16	05
	741	0	14	64
	757/1 to 6	0	03	90
	767/2	0	08	10
	667/1	0	09	98
	766	0	01	12
	934	0	16	20
	773/2	0	00	10
	773/3	0	05	08
	773/1	0	04	50
	9 5/10	0	09	92
	905/9	0	00	49
	930/1	0	00	95
	905/2	0	09	90
	929	0	16	65
	925/4	0	03	68
	926	0	08	76
	921/1	0	01	56
	991	0	00	03
	992	0	04	68
	996	0	01	44
	995/2/2	0	03	41
	905/1	0	04	95
	995/2/1	0	04	92
	997	0	00	08
	994	0	06	95
	1128/1+2	0	02	18
	1126	0	07	56
	1127	0	06	27
	1 29/4	0	00	86
	1129/2	0	04	95
	1129/1	0	07	22
	1130/1/1	0	00	75
	1125	0	06	46
	1123	0	06	23
	1124	0	00	06
	1122	0	00	05
	1121	0	11	38
	1115	0	13	05
	1117	0	00	03
	1112/1	0	02	16
	1116/2	0	06	30
	1110/6	0	04	06
	1110/5	0	00	14
	1109/2	0	04	65

1	2	3	4	5	2	3	4	5
					CART TRACK	0	00	95
1109/1		0	04	80	2114	0	06	30
1108/1/1		0	09	49	2113	0	23	30
1089		0	05	90	[No. 12016/15/82—Prod.I]			
1106		0	04	65	नई दिल्ली, 10 मई, 1982			
1090		0	02	89	का० आ० 1913—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 190 तारीख 1-1-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।			
1105		0	01	53	और यतः समस्त प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्टें दे दी हैं।			
1091		0	06	06	और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।			
1092/1+2		0	04	50	अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।			
1093		0	07	88	और प्रागे उस धारा की उप धारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा			
1094		0	10	47	अनुसूची			
1097		0	00	68	कूप न० 83 से बूथ न० 2 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।			
1095		0	03	53	राज्य : गुजरात जिला : भरुच ताल्लुका : धंक्सेश्वर			
1096		0	08	32				
1055/5		0	10	73				
1591/1+2+3		0	00	33				
1592/1		0	09	95				
1592/2		0	00	24				
1594		0	00	05				
1593/3		0	09	80				
1593/1		0	00	04				
1603		0	34	43				
1607/3		0	01	80				
1607/2		0	09	55				
1659		0	04	35				
1657		0	05	76				
1658		0	08	25				
1710		0	06	11				
1711/1		0	08	03				
1711/3		0	00	12				
1711/4		0	04	59				
1714/2		0	01	70				
1713/2		0	08	35				
1713/1		0	05	03				
1721		0	07	35				
1726		0	03	15				
1725		0	06	75				
1723/1		0	05	95				
1722/2		0	00	60				
1722/1		0	10	20				
1720		0	03	01				
1749		0	04	39				
1773/3		0	05	70				
1773/1		0	05	64				
1773/2		0	00	06				
1776/1		0	12	13				
1775		0	01	52				
1790		0	03	83				
1778		0	10	88				
1788/2/2		0	03	38				
1779/1		0	08	98				
1787		0	14	92				
1811		0	01	10				
1786		0	00	37				
1812		0	07	58				
1813		0	01	43				
1824		0	40	33				
1815		0	01	22				
1823		0	01	43				
1822		0	03	98				
1821		0	08	03				
1828		0	15	23				
1830		0	07	14				
CART TRACK		0	04	16				
1838		0	03	12				
1833		0	22	97				
1832		0	01	44				

[सं० 12016/59/81-प्र० II]

New Delhi, the 10th May, 1982

S.O. 1913.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 190 dated 1-1-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the

schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And Whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And Further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, Therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL No. 83 TO BOOTH No. 2.
STATE : GUJARAT DISTRICT : BHARUCH
TALUKA : ANKLESHWAR

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Sarthan	352	0	04	16
	364	0	10	27
	368	0	11	31
	369	0	17	42
	376	0	07	08
	376	0	14	69
	489	0	10	40
	592	0	09	62
	591	0	04	55
	587	0	21	71
	579	0	15	60
	577	0	03	90
	5.6A	0	09	75
	564	0	01	30

[No. 12016/59/81-Prod.III]

का० आ० 1914—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 189 तारीख 1-1-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का

अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तब और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, बोधवा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० 122 से 21 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : भरुच	तालुका : अंकलेश्वर	गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	ए. आर. ई.	सेंटीयर
			अडोल	329	0	01	82
				333	0	19	50
				334	0	02	34

[सं० 12016/59/81-प्रो० I]

S.O. 1914.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 189 dated 1-1-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 122 to 21

Sate : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
ADOL	329	0	01	82
	333	0	19	50
	334	0	02	34

[No. 12016/59 81—P rod.-I]

का० आ० 1915 —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2383 तारीख 20-8-81 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

शालोरा 12 से शालोरा जी० जी० एस-1

राज्य :	गुजरात	जिला . मेहसाना	तालुका : कडी	
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए. आर. ई.	सेटीयर
मेरडा	174	0	13	95
	176	0	06	00
	177	0	03	00
	175	0	07	50
	180	0	16	50
	181	0	21	00
	87	0	07	50
	91	0	12	75
	193	0	12	75
	80	0	04	00

[सं० 12016/24/81-प्रो०]

S.O. 1915.—Where by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 2383 dated 20-8-81 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline-;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Jhalora 12 To Jhalora GGS I

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centa	fire
1	2	3	4	5	
MERDA	174	0	13	95	
	176	0	06	00	
	177	0	03	00	
	175	0	07	50	

1	2	4	4	5
	180	0	16	50
	181	0	21	00
	87	0	07	50
	91	0	12	75
	193	0	12	75
	80	0	04	00

[No. 12016/24/81—Prod].

का० आ० 1916—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3128 तारीख 20-8-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः समक्ष प्रधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

सी० टी० एफ० कालो से दक्षिण कडी तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला . मेहसाना/तहसील : कालो

गांव	कॉक नं०	हेक्टेयर	आर	सेटीयर
पीयज	454	0	02	60
	453	0	07	10
	452	0	05	10
	448	0	02	25
	445	0	11	20
	449	0	17	05
	418	0	05	45
	420	0	00	50
	419	0	05	75
	404	0	05	35
	408	0	02	25
	406	0	04	25
	405/1	0	01	75
	368	0	03	75
	294	0	05	15

1	2	3	4	5	SCHEDULE				
	KANS	0	00	80	Pipeline	From CTF Kalol	to South Kadi		
	295	0	05	80	State : Gujarat	District : Mchana	Taluka : Kalol		
	296	0	07	15	Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
	297	0	01	00	PIEJ	454	0	02	60
	298	0	01	25		453	0	07	10
	299	0	00	60		452	0	05	10
	300	0	00	50		448	0	02	25
	301	0	02	05		445	0	11	20
	काट ट्रैक	0	00	65		449	0	17	05
	255	0	00	25		418	0	05	45
	254	0	04	50		420	0	00	50
	253	0	06	70		419	0	05	75
	252	0	02	65		404	0	05	35
	251	0	03	65		408	0	02	25
	249	0	00	60		406	0	04	25
	248	0	08	75		405/1	0	01	75
	226	0	04	10		368	0	03	75
	227	0	02	00		294	0	05	15
	228	0	03	00		KANS	0	00	80
	229	0	00	40		295	0	05	80
	213	0	03	25		296	0	07	15
	205	0	12	70		297	0	01	00
	काट ट्रैक	0	00	30		298	0	01	25
	206	0	00	30		300	0	00	50
	194	0	00	40		299	0	00	60
	192	0	02	00		301	0	02	05
	191	0	07	05		CART TRACK	0	00	65
						255	0	00	25
						254	0	04	50
						253	0	06	70
						252	0	02	65
						251	0	03	65
						249	0	00	60
						248	0	08	75
						226	0	04	10
						227	0	02	00
						228	0	03	00
						229	0	00	40
						213	0	03	25
						205	0	12	70
						CART TRACK	0	00	30
						206	0	00	30
						194	0	00	40
						192	0	02	00
						191	0	07	05

[सं० 12016/32/79-प्रो०]

एल० एम० गोयल, निदेशक

S.O. 1916.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer (Department of Petroleum), S.O. No. 3128 dated 20-8-79 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

[No. 12016/32/79—PROD.]

L. M. GOYAL, Director

नई दिल्ली, 6 मई, 1982

का० आ० 1917.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3131 तारीख 20-8-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को प्राप्त लाईनों का बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा प्रजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

सी० टी० एफ० कलोल से दक्षिणी कड़ी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला मेहसाना तहसील कड़ी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	भार	सेंटीमीटर
लुनासन	257	0	04	00
	258	0	06	00
	260	0	04	35
	269	0	01	65
	268	0	06	10
	267	0	00	60
	263	0	07	35
	307	0	03	75
	264	0	01	05
	308	0	00	95
	306	0	06	10
	304	0	03	25
	302	0	03	00
	301	0	02	50
	317	0	01	55
	318/2	0	02	60
	318/1	0	03	90
कोर्ट ट्रैक	0	00	30	
350	0	07	80	
कार्ट ट्रैक	0	00	35	
431/1	0	04	35	
431/2	0	02	30	
450/2	0	03	85	
449	0	04	70	
कार्ट ट्रैक	0	00	40	
447/1	0	01	00	
446	0	04	00	
445	0	02	15	
444/1	0	02	40	
कार्ट ट्रैक	0	00	60	
462	0	02	90	
461	0	01	75	
471	0	05	55	
472	0	08	10	
473	0	00	15	

[सं० 12016/38/79-प्र० I]

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From CTF Kalol to South Kadi
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
LUNASAN	257	0	04	00
	258	0	06	00
	260	0	04	35
	269	0	01	65
	268	0	06	10
	267	0	00	60
	263	0	07	35
	307	0	03	75
	264	0	01	05
	308	0	00	95
	306	0	06	10
	304	0	03	25
	302	0	03	00
	301	0	02	50
	317	0	01	55
	318/2	0	02	60
	318/1	0	03	90
	Cart Track	0	00	30
	350	0	07	80
	Cart track	0	00	35
	431/1	0	04	35
	431/2	0	02	30
	450/2	0	03	85
	449	0	04	70
	Cart track	0	00	40
	447/1	0	01	00
	446	0	04	00
	445	0	02	15
	444/1	0	02	40
	Cart track	0	00	60
	462	0	02	90
	461	0	01	75
	471	0	05	55
	472	0	08	10
	473	0	00	15

[No. 12016/38/79—PROD.]

S.O. 1917.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer (Department of Petroleum), S.O. No. 3131 dated 20-8-79 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and

कांश० 1918:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना कांश० सं० 3132 तारीख 20-8-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से दक्षिण कड़ी तक पाइप बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात,	जिला मेहसाना,	तहसील कड़ी			
गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	घार	सेन्टीयर	
करमतनगर	212	0	02	80	
	211	0	00	55	
	213	0	01	15	
	207/4	0	09	50	
	207/3	0	04	30	
	207/2	0	04	25	
	207/1	0	03	50	
	235	0	04	00	
	236	0	04	40	
	237	0	03	65	
	264	0	00	25	
	265	0	01	85	
	201	0	02	90	
	191	0	03	50	
	193/1	0	10	15	
	195	0	04	00	
	197/1	0	02	50	
	कार्टट्रेक	0	00	40	
	176	0	04	30	
	175	0	02	60	
	174	0	00	90	
	171	0	08	75	
	170	0	03	75	
	168	0	00	95	
	157	0	03	00	
	158	0	03	05	
	159	0	02	70	

160/1	0	02	10
164/2	0	00	15
162	0	06	45

[सं० 12016/38/79—प्रो०—II]

S.O. 1918.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum), S.O. No. 3132 dated 20-8-79 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From CTF Kulol to South Kadi				
State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
KARAN NAGAR	212	0	02	60
	211	0	00	55
	213	0	01	15
	207/4	0	09	50
	207/3	0	04	30
	207/2	0	04	25
	207/1	0	03	50
	235	0	04	00
	236	0	04	40
	237	0	03	65
	264	0	00	25
	265	0	01	85
	201	0	02	90
	191	0	03	50
	193/1	0	10	15
	195	0	04	00
	197/1	0	02	50
	Cart Track	0	00	40
	176	0	04	30
	175	0	02	60
	174	0	00	90
	171	0	08	75
	170	0	03	75
	168	0	00	95
	157	0	03	00
	158	0	03	05
	159	0	02	70
	160/1	0	02	10
	164/2	0	00	15
	162	0	06	45

[No. 12016/38/79—PROD. II]

नई दिल्ली, 10 मई, 1982

का०आ० 1919:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मुदाना-1 से दक्षिण संथाल जी०जी०एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

मुदाना-1 से दक्षिण संथाल जी०जी०एस०

राज्य : गुजरात

जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एग्राई	सेन्टीयर
कसलपुरा	902	0	00	75
	847/पी	0	04	20
	847/पी	0	01	60
	848	0	15	55
	850	0	12	40
	851	0	05	90

[सं० 12016/1/82/प्रो०-1]

New Delhi, the 10th May, 1982

S.O. 1919.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Jotana-1 to S. Santhal GGS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Jotana-1 To S. Santhal GGS

State : Gujarat

District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-arc
1	2	3	4	5
Kasulpura	902	0	00	75
	947/P	0	04	20
	847/P	0	01	60
	848	0	15	55
	850	0	12	40
	851	0	05	90

[No. 12016/1/82/Prod.]

का०आ० 1920:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दक्षिण संथाल जी०जी०एस० से उत्तर जी०जी०एस०-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

दक्षिण संथाल जी०जी०एस० से उत्तर कड़ी जी०जी०एस०-1

राज्य : गुजरात

जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एग्राई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मुदाना	1126	0	01	45
	1125	0	03	00
	1124	0	01	50
कार्ट ट्रेक		0	00	20
	1123	0	02	60
	1088	0	02	65
	1089	0	01	75
	1085	0	01	75
	1083	0	02	75
	1082	0	03	10
	1081	0	01	50
	1080	0	01	50
	1071	0	03	00

1	2	3	4	5
	1072	0	02	25
	1073	0	02	05
	1057	0	01	30
	1056	0	02	60
	1054	0	02	90
	1059	0	00	70
	काट ट्रेक	0	00	25
	1023	0	06	40
	1021	0	03	35
	1018	0	02	20
	990	0	12	30

[सं० 12016/1/82/प्रो०-2]

S.O. 1920.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from South Santhal GGS to N.K. GGS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From South Santhal GGS to NK, GGS I
State : Gujarat District and Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centi-are
JOTANA	1126	0	01	45
	1125	0	03	00
	1124	0	01	50
	Cart Track	0	00	20
	1123	0	02	60
	1088	0	02	65
	1089	0	01	75
	1085	0	01	75
	1083	0	02	75
	1082	0	03	10
	1081	0	01	50
	1080	0	01	50
	1071	0	03	00
	1072	0	02	25
	1073	0	02	05
	1057	0	01	30
	1056	0	02	60
	1054	0	02	90
	1059	0	00	70
	Cart track	0	00	25
	1023	0	06	40
	1021	0	03	35
	1018	0	02	20
	980	0	12	30

[No. 12016/1/82/Prod-1]

का० आ० 1921—यत्. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2789 तारीख 26-9-81 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों का बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत्. समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन० एन० घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वण देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

खालोरा—12 में जी० जी० एस० खालोरा				
राज्य	गुजरात	जिला मेहसाना	तालुका :	कड़ी
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आई ई	सेटीमीटर
भाद्रज	1705/2	0	17	50
	1706	0	12	20
	1709	0	01	35
	1708/1	0	04	50
	1708/2/B	0	03	75
	1710	0	11	43
	1720	0	07	60
	1711/2	0	01	50
	1712/1	0	06	30
	1714	0	04	20
	1715	0	09	00
	1717/1	0	11	55
	काट ट्रेक	0	00	85
	1603	0	09	00

[सं० 12016/29/81-प्रो०]

टी० एन० परमेश्वरन्, अवर सचिव

S.O. 1921.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers, (Department of Petroleum) S.O. 2789 dated 26-9-81 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest, on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Jhalora -12 To GGS Jhalora

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka	Kadi
Village	Survey No	Hectare	Are
ADRAJ	1705/2	0	17
	1706	0	12
	1709	0	01
	1708/1	0	04
	1708/2/B	0	03
	1710	0	11
	1726	0	07
	1711/2	0	01
	1712/1	0	06
	1714	0	04
	1715	0	09
	1717/1	0	11
	Cut track	0	00
	1603	0	09

[No. 12016/29/80-Prod.]

T N PARAMESWARAN, Under Secy

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 1982

का०आ० 1922.—यत् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धा के अनुसरण में मैसूर विश्व-विद्यालय ने डा० एन० यैकर नायक को 22 मार्च, 1982 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मन्त्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59एम-1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में 'धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित' शीर्ष के अन्तर्गत क्रम सं० 20 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् —

"20. एन० यैकर नायक,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, शरीर रचना विज्ञान, विभाग,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज,
मैसूर-570001, कर्नाटक राज्य"

[सं० बी० 11013/14/80-एम०ई०(पी)]

प्रकाश चन्द्र जैन, अधीक्षक सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 11th May, 1982

S.O. 1922.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (4) of section 7 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr N Thacker Naik has been elected by the Mysore University to be member of the Medical Council of India with effect from the 22nd March, 1982.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the late Ministry of Health No 5-13/59-MI dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 20 and entry relating thereto the following serial number and entry shall be submitted namely :—

"20 Dr N Thacker Naik,
Professor and Head of the Department of Anatomy,
Government Medical College, Mysore-570001.
Karnataka State"

[No. V 11013/14/80 M E (Policy)]
P C JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मई, 1982

का० आ० 1923.—यत् केन्द्रीय सरकार ने वन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 10) की धारा 3 के खण्ड (च) के अनुसरण में मेजर जनरल पी०सी० कोछड़, निदेशक, दंत चिकित्सा सेवा, चिकित्सा निदेशालय, सशस्त्र सेना मुख्यालय, नई दिल्ली को पहली अक्तूबर, 1981 से भारतीय दंत चिकित्सा परिषद का सदस्य मनोनीत किया है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 9 फरवरी, 1978 की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 533 में पुनः प्रकाशित भारत सरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मन्त्रालय की 12 अप्रैल, 1942 की अधिसूचना संख्या एफ० 10-10 48 एम 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में 'धारा 3 के खण्ड (च) के अधीन मनोनीत' शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् —

"3 मेजर जनरल पी०सी० कोछड़, केन्द्रीय सरकार 1-10-1981"
निदेशक,
दंत चिकित्सा सेवा
चिकित्सा निदेशालय
सशस्त्र सेना मुख्यालय,
नई दिल्ली।

[सं० बी० 12013/3/82 पी०एम०एस०(फोल्डर-4)]
एन०ए० सुब्रह्मण्य, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 11th May, 1982

S.O. 1923:—Whereas the Central Government have in pursuance of clause (f) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) nominated Major General P C Kochar, Director, Dental Service, Medical Directorate Army Headquarters, New Delhi to be a member of the Dental Council of India, with effect from the 1st October, 1981 upto 30th September, 1986

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No F 10-10/48-MI dated the 12th April 1949, as republished in the Ministry of Health and Family Wel-

fare (Department of Health) Notification No. SO 533, dated the 9th February, 1978, namely:—

In the said notification under the heading Nominated under clause (f) of section 3" for serial number 3 and the entries relating to the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
"3	General Major P.C. Kochhar, Director, Dental Services, Medical Directorate Army Headquarters, New Delhi.	Central Government	1-10-1981"

[No. V. 12/13/31-PMS(Folder VI)]
N. A. SUBRAMONEY, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, 1 मई, 1982

का०आ० 1924— केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (भर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1408 तारीख 6 मार्च, 1981 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 960.00 एकड़ (लगभग) या 388.49 हेक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 954.70 एकड़ (लगभग) या 386.35 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का भर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण-1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण, उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1— कार्डविल हाउस स्ट्रीट, फलकला-1 के कार्यालय में अथवा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण-2 कोयला धारक क्षेत्र (भर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है—

“8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हिनवद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीन दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का भर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

- स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थात्सर्गेत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयंखान संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के प्रभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिर्णय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हिनवद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।”

टिप्पण-3 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, कार्डविल हाउस स्ट्रीट, फलकला की उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

घोरला ब्लॉक

(पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र)

जिला हजारीबाग

(बिहार)

ग्रांथ सं० राजस्व 5/82
तारीख 11 जनवरी, 1982

सभी अधिकार
उप-ब्लॉक “क”

जिसमें अर्जित की जाने वाली
भूमि दर्शित की गई है।

हॉसं०	ग्राम	घाना	घाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	कुजु	मांडू	154	हजारीबाग	334.00	भाग
2.	मुरपा	मांडू	155	हजारीबाग	222.70	भाग
3.	भारा	मांडू	156	हजारीबाग	75.00	भाग
कुल क्षेत्र 631.70 एकड़ (लगभग)						
या 255.64 हेक्टर (लगभग)						

ग्राम कुजु में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

294(भाग), 296(भाग), 320(भाग), 321(भाग), 322(भाग), 323 से 328, 329(भाग), 330 से 333, 334(भाग), 335(भाग), 1009(भाग), 1011(भाग), 1019(भाग), 1020(भाग), 1024(भाग), 1025 से 1032, 1033(भाग), 1034 से 1088 और 1089 (भाग),

ग्राम मुरपा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक

2(भाग), 10(भाग), 11(भाग), 12(भाग), 13, 14, 15, 16(भाग), 17(भाग), 25(भाग), 28 से 40, 41(भाग), 42, 43, 44(भाग), 49(भाग), 50 से 55, 56(भाग), 57(भाग), 58 से 63, 64(भाग), 66 से 79, 80(भाग), 81, 82, 83, 84, 85(भाग), 105(भाग), 167 (भाग), 181(भाग), 256(भाग), 257(भाग), 258 से 297, 298 (भाग), 299 से 302, 303 (भाग), 370(भाग) और 968।

ग्राम भारा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक

871 (भाग), 872 (भाग), 1286 (भाग), 1287 (भाग) और 1294 (भाग)

सीमा वर्णन

उप-ब्लाक 'ख'

क-ख रेखा ग्राम कुजु में (सड़ग नेशनल हाइवे) के भागत: पूर्वी पार्श्व के साथ साथ जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

ख-ग रेखा ग्राम कुजु में प्लाट संख्यांक 1033, 1008, 1011, 1024, 1033, 1020, 1019, 1033 और 1089 से होकर जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग-घ, रेखा ग्राम कुजु और मुरपा को भागत: सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ-ङ रेखा ग्राम मुरपा में के प्लाट संख्यांक 105, 85, 80, 167 से होकर फिर प्लाट संख्यांक 166 और 65 को उत्तरी सीमा के साथ साथ, प्लाट संख्यांक 64 से होकर प्लाट संख्यांक 58 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ, प्लाट संख्यांक 57, 58, 181, 49 से होकर, प्लाट संख्यांक 2 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ, प्लाट संख्यांक 49 से होकर प्लाट संख्यांक 43 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्यांक 41, 44, 256, 257, 2, 298, 2, 303 और 370 से होकर जाती है और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।

ङ-च रेखा ग्राम मुरपा और धारा का भागत: सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है।

च-छ रेखा ग्राम धारा के प्लाट संख्यांक 1294, 1287 और 1286 से होकर जाती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।

छ-ज रेखा ग्राम धारा के प्लाट संख्यांक 1286, 872 और 871 से होकर जाती है (जो धारा कोयला खान पट्टाधृति के साथ भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

ज-झ रेखा ग्राम धारा और मुरपा को भागत: सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है (जो धारा कोयला खान पट्टाधृति सीमा की भागत: सम्मिलित सीमा भी है) और बिन्दु 'झ' पर मिलती है।

झ-ञ-ट रेखाएं ग्राम मुरपा के प्लाट संख्यांक 2, 25, 2, 17, 16, 2, 11, 2, 10, 2, 12 और 2 से होकर और ग्राम कुजु के प्लाट संख्यांक 322 से होकर जाती है (जो मुरपा कोयला खान पट्टाधृति सीमा के साथ भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'ट' पर मिलती है।

ट-क रेखा ग्राम कुजु के प्लाट संख्यांक 294, 296, 320, 322, 321, 325, 329, 335, 334 और 329 से होकर जाती है (जो कुजु कोयला खान पट्टाधृति सीमा के साथ भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है, और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	ओरला	मांहु	128	हजारीबाग	110.00	भाग
2.	कुजु	मांहु	154	"	213.00	भाग

कुल क्षेत्र : 323.00 एकड़ (लगभग)

या : 130.71 हेक्टर (लगभग)

ग्राम ओरला में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 785 भाग, 787 से 792 तक और 889

ग्राम कुजु में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

19 (भाग), 364 (भाग), 365 से 394, 395, 396 से 473, 474 (भाग), 475 (भाग), 476 (भाग), 477 (भाग), 485 (भाग) 486 (भाग), 487, 488, 489, (भाग) 490 491 (भाग), 493 (भाग) 494, 495, 496, 497, (भाग), 498 (भाग), और 507 (भाग),

सीमा वर्णन

ठ-ड रेखा ग्राम कुजु के प्लाट संख्यांक 364 और 19 से होकर जाती है (जो कुजु कोयला खान पट्टाधृति सीमा के साथ भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

ड-ड रेखा नाले की भागत: मध्य रेखा के साथ साथ जाती है (जो ग्राम कुजु और बनवार की भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है) और बनवार कोयला खान पट्टाधृति सीमा के साथ भागत: सम्मिलित सीमा भी बनाती है और बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

ड-ण रेखा ग्राम ओरला और बनवार की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है (जो बनवार कोयला खान पट्टाधृति सीमा के साथ भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'ण' पर मिलती है।

ण-त रेखा ग्राम टोपा और ओरला की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है (जो टोपा कोयला खान पट्टाधृति सीमा के साथ भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'त' पर मिलती है।

त-थ-द रेखाएं ग्राम ओरला के प्लाट संख्यांक 785 से होकर जाती है और बिन्दु 'द' पर मिलती है।

द-ध रेखा ग्राम ओरला और कुजु की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु 'ध' पर मिलती है।

ध-न रेखा ग्राम कुजु के प्लाट संख्यांक 395, 474, 475, 395, 476, 477, 486, 485, 489, 491, 493, 497, 498, और 507 से होकर जाती है और बिन्दु 'न' पर मिलती है।

न-ड रेखा ग्राम कुजु में नेशनल हाइवे रोड के भागत: पश्चिमी पार्श्व के साथ साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

[म० 19/30/82-सी (एन)]

स्वर्ण सिंह, अधीक्षक सचिव,

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 1st May, 1982

S.O.1924 —Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No S O 1408 dated the 6th March, 1981, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 960 00 acres (approximately) or 388 49 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the schedule appended to that notification.

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in part of the said lands,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 954 70 acres (approximately) or 386 35 hectares (approximately) described in the schedule appended hereto.

Note 1 The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House street, Calcutta-1 or in the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar)

Note 2 Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957) which provides as follows —

8 (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land of any rights in or over such land.

Explanation It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different report in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such lands were acquired under this Act "

Note 3 The coal Controller, 1, Council House street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the Competent authority under the Act

SCHEDULE

Drg No Rev/5/82

Dated 11-1-82

(Showing lands to be acquired)

Orla Block

(West Bokaro Coalfield)

All Rights		Distt Hazaribagh				
Sub Block A		Bihar				
Serial number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1	Kuju	Mandu	154	Hazaribagh	334 00	part
2	Murpa	Mandu	155	Hazaribagh	222 70	part
3	Ara	—do—	156	—do—	75 00	—do—
Total area				— 631 70 acres (approximately)		
or				255 64 hectares (approximately)		

Plot numbers to be acquired in village Kuju —294 (part), 296 (part), 320 (part) 321 (part), 322 (part), 323 to 328, 329 (part), 330 to 333, 334 (part), 335 (part), 1008 (part), 1011 (part), 1019 (part), 1020 (part), 1024 (part), 1025 to 1032, 1033 (part), 1034 to 1088 and 1089 (part)

Plot numbers to be acquired in village Murpa —2(part), 10(part), 11(part), 12(part), 13, 14, 15, 16 (part), 17(part), 25(part), 26 to 40, 41(part), 42, 43, 44(part), 49(part), 50 to 55, 56(part), 57(part), 58 to 63, 64(part), 66 to 79, 80(part), 81, 82, 83, 84, 85(part), 105(part), 167(part), 181(part), 256(part), 257(part), 258 to 297, 298 (part), 299 to 302, 303 (part), 370 (part) and 968

Plot numbers to be acquired in village Ara — 871(part), 872 (part), 1286(part), 1287(part), and 1294(part)

Boundary Description:—

A—B	Line passes along the part eastern side of Road (National Highway) in village Kuju and meets at point 'B'
B—C	Line passes through plot numbers 1033, 1008, 1011, 1024, 1033, 1020, 1019, 1033 and 1089 in village Kuju and meets at Point 'C'.
C—D	Line passes along the part common boundary of villages Kuju and Murpa and meets at point 'D'
D—E	Line passes through plot numbers 105, 85, 80, 117, then along the northern boundary of plot numbers 166 and 63 through plot nos 64 along southern boundary of plot No. 58 through plot nos 57, 56, 181, 49 along southern boundary of plot no 2, through plot nos 49 along southern boundary of plot no 43, through plot nos, 41, 44, 256, 257, 2, 298, 2, 303 and 370 of village Murpa and meets at point 'E'
E—F	Line passes along the part common boundary of villages Murpa and Ara and meets at point 'F'
F—G	Line passes through plot numbers 1294, 1287 and 1286 of village Ara and meets at point 'G'
G—H	Line passes through plot numbers 1286, 872 and 871 of village Ara (which forms part common boundary with Ara Colliery leasehold boundary) and meets at point 'H'
H—I	Line passes along the part common boundary of villages Ara and Murpa (which is also part common boundary of Ara Colliery leasehold boundary) and meets at point 'I'
I—J—K	lines pass through plot numbers 2, 25, 2, 17, 16, 2, 11, 2, 10, 2, 12 and 2 of village Murpa and through plot no 322 of village Kuju (which forms part common boundary with Murpa Colliery leasehold boundary) and meets at point 'K'

K—A line passes through plot numbers 294, 296, 320, 322, 321, 322, 329, 335, 334 and 329 of village Kuju (which forms part common boundary with Kuju colliery leasehold boundary) and meets at starting point 'A'.

Sub-Block 'B'

S. No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1.	Orla	Mandu	128	Hazaribagh	110.00	part
2.	Kuju	-do-	154	-do-	213.00	part
Total Area :-323.00 acres (approximately) or 130.71 hectares (approximately)						

Plot numbers to be acquired in village Orla :-
785 (part), 787 to 792 and 889.

Plot numbers to be acquired in village Kuju :-

19 (part), 364 (part) 365 to 394, 395 (part), 396 to 473, 474 (part), 475 (part), 476 (part), 477 (part), 485 (part), 486 (part) 487, 488, 489 (part), 490, 491 (part), 493 (part), 494, 495, 496, 497 (part), 498 (part) and 507 (part).

Boundary Description :-

L—M line passes through plot numbers 364 and 19 of village Kuju (which forms part common boundary with Kuju Colliery leasehold boundary) and meets at point 'M'.

M—N line passes along the part central line of Nalla (which forms part common boundary of villages Kuju and Banwar) and also forms part common boundary with Banwar Colliery leasehold boundary and meets at point 'N'.

N—O line passes along the common boundary of villages Orla and Banwar (which forms part common boundary with Banwar Colliery leasehold boundary) and meets at point 'O'.

O—P line passes along the part common boundary of village Topa and Orla (which forms part common boundary with Topa Colliery leasehold boundary) and meets at point 'P'.

P—Q—R lines pass through plot number 785 of village Orla and meets at point 'R'.

R—S line passes along the part common boundary of villages Orla and Kuju and meets at point 'S'.

S—T line passes through plot numbers 395, 474, 475, 395, 476, 477, 486, 485, 489, 491, 493, 497, 498 and 507 of village Kuju and meets at point 'T'.

T—L line passes along the part western side of National Highway Road in village Kuju and meets at starting point 'L'.

[No. 19/30/82-CL]

SWARAN SINGH, Under Secy.

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1982

कां. भां. 1925.—सरकारी स्थान (प्रसाधिकृत अधिसूचियों की वेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे की तालिका के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारों को राष्ट्रीय ताप विद्युत विभाग एक निगमित निकाय का अधिकारी होने के कारण तथा भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के स्तर के समकक्ष स्तर का अधिकारी होने के कारण उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मध्यम अधिकारी नियुक्त करती है। यह अधिकारी उक्त तालिका के कालम 3 में संबंधित प्रविष्टि में निविष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत उपरोक्त अधिनियम के द्वारा प्रदत्त उसके अन्तर्गत संपदा अधिकारों को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा।

तालिका

कॉ.सं. अधिकारी का पद सरकारी स्थानों की श्रेणियां तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं

1. श्री एच.एस. भट्टाल बरिष्ठ नदरपुर ताप विद्युत केन्द्र तथा बररपुर ताप विद्युत परियोजना, नई दिल्ली के स्वाभिव में उनके द्वारा पट्टे पर की गई या किराये पर ली गई सभी भूमिया ब्याटर संपदा सम्पत्तियां तथा अन्य प्राप्तियां तथा इनके स्टॉक कालोनियों तथा शापिंग सेक्टर भार औद्योगिक कार्य कालानों तथा मोलार बैंड अमिह कालाना

[सं. 5(5)/81-यू.एस.डी.सी.-I]

अजिन्द्र वीर, धरर सचिव

(Department of Power)

New Delhi, the 23rd April, 1982

S.O. 1925.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (2) of the Table below, being an officer of the National Thermal Power Corporation Limited, a Corporate authority, and being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government of India, to be the estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on an estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction, in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Designation of Officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Shri H.S. Bhattal Senior Law Officer	All lands, quarters, estate, properties and other accommodations owned, leased or rented by the Badarpur Thermal Power Station and Badarpur Thermal Power Project, New Delhi and their staff colonies and shopping Centres, Bharat Industrial Works Colony and Molarband Labour Colony.

[No. 5(5)/81-USDV-I]

JATINDER VIR, Under Secy.

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली 28 अप्रैल, 1982

कां.भां. 1926.—केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्रह्मपुत्र बाढ़ी की सीमाओं का अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हमसे उपायय नक्शे में दिए रूप में सीमांकन करती है।

[सं. 2/81-बी.सी.]

सु. कृ. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 28th April, 1982

S.O. 1926.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 11 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980), the Central Government hereby demarcates for the purposes of the Act, the limits of the Brahmaputra Valley as outlined in the map annexed hereto.

[No. 2/81-B.C.]

S. K. AGGARWAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th May, 1982

S.O. 1927.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra (South) Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhowra, District Dhanabad and their workman, which was received by the Central Government on the 11th May, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 41/80

PRESENT :

Shri J. N. Singh,
Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhowra (South) Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Bhowra, Dist. Dhanbad.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workman—Shri J. D. Lal, Advocate.

INDUSTRY : Coal

STATE : Bihar

Dated, the 4th May, 1982

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(9)/80-D.III(A) dated the 6th June, 1980.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Bhowra (South) Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Bhowra, Dist. Dhanbad in striking off the name of Shri Srinivas Singh Bhatta Supervisor with effect from the 16th October, 1976, is justified. If not, to what relief is the said workman entitled?”

2. The case of the workman is that he was working as Bhatta Supervisor in Bhowra (S) Colliery since 1969 and was a permanent workman of the colliery. It is stated that he fell sick on 15-6-76 and he informed the management accordingly and prayed for grant of leave till his recovery. He sent an application dated 10-10-76 to the management enclosing the medical certificate but no reply was given to him. The management however by a letter dated 16-10-76 informed the concerned workman that his name had been struck off from rolls of the colliery. The concerned workman sent a representation dated 2-11-76 protesting against such illegal action of the management to which no reply was received.

3. It is then alleged that Shri Srinivas Singh the workman concerned reported for duty in the colliery on 28-2-78 after his recovery and also enclosed his fitness certificate but he was not allowed to join. He then made representation through the Union and thereafter raised the present industrial dispute. The conciliation ended in failure and hence this Reference.

187 GI/83—5

4. It is submitted that the action of the management in striking off the name of the concerned workman is illegal and against law. There was no provision in the standing order which contains the terms and conditions of service that the name of a workman would be struck off for being absent for more than 10 days. This action utmost amounted to a misconduct for which chargesheet should have been drawn and a proper enquiry should have been conducted. But no chargesheet was ever issued against the concerned workman nor any departmental enquiry was conducted against him and hence the action of the management is void and illegal as the said action amounted to retrenchment for which no compensation was paid U/S 25F of the Industrial Disputes Act. It is also submitted that the provision of Section 25-N was also not complied with. It is therefore submitted that the concerned workman is entitled to be reinstated with full back wages.

5. The defence of the management is that the present reference is not legally maintainable as the concerned workman was a Bhatta Supervisor and was performing supervisory duties and was drawing more than Rs. 500/- and hence he was not a workman within the meaning of Industrial Disputes Act. It is further stated that the concerned workman was not found on duty on 16-6-76 and on enquiry it was revealed that he had left the colliery without any permission or authorised leave. He was sent a letter dated 16-7-76 directing him to report for duty without fail and finally when no response was made a letter was issued by the management dated 16-10-76 intimating him that his name had been struck off from the roll on the presumption that he had voluntarily left his job. The management also learnt that he had taken up employment elsewhere. It is further stated that it was only after a lapse of two and a half years that Sri J. D. Lal sent a letter dated 9-12-78 stating that the concerned workman was ill from 16-6-76 and he reported for duties on 28-2-78 but was not allowed to join.

6. The concerned workman, however, has denied that he was employed anywhere, else as contended by the management. According to the management however as the concerned workman absented for a long time and so abandoned his job and hence his name was struck off from the rolls of the colliery and no illegality had been committed by the management.

7. The point for consideration is as to whether the action of the management in striking off the name of the concerned workman with effect from 16-10-76 is justified. If not, to what relief is the said workman entitled.

8. I will first take up preliminary issue raised by the management as to whether the concerned workman is a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act or not. The concerned workman has examined himself as WW-1 and he was stated that his duty was to put attendance of workers and to maintain log book. According to him the log book contain the amount of output. He has further stated that his pay was less than Rs. 500 per month and that he was in clerical Grade II and not in supervisory grade as contended on behalf of the management. It is stated on his behalf that if he would have been in supervisory grade then he must have received the pay of supervisory grade as recommended by the Coal Wage Board recommendation.

9. In support of it the concerned workman has also filed his pay sheet Ext. W-2 for the month of February 76 which shows his gross earning was at Rs. 481.19 paise. Ext. W-1 is his identity card. This pay slip has been challenged on behalf of the management and it is stated that it is not correct, but the pay slip has been prepared by computer and I find no reason to disbelieve its genuineness.

10. As against this the management has filed the bonus register for the year 1975 page 91 of which would indicate that the average pay of the concerned workman including overtime etc. was more than Rs. 500 from the month of March '75 to June '75 but this bonus register is not of the relevant period.

11. Now even if it be conceded that the concerned workman was getting more than Rs. 500 still it is to be decided as to whether he will come within the meaning of workman or not. It is well settled that the mere designation by which a person is designated is not conclusive of his status and the Industrial Court has to look to the nature of the duties assigned to the person concerned to decide whether he is a workman or not. To support this view reference may be made to the ruling reported in 5 S.C.L.J., page 3547 (Syndicate Bank Ltd., and its workmen). In the ruling reported in 2 S. C. L. J., page 1023 (Indian Iron & Steel Co. Ltd., and another and their workman) it has been held that where the manager of a hotel belonging to the company had also to write ledger, file correspondence, enter the cash book etc. his duties were held to be not merely supervisory in nature but he was held to be workman within the meaning of the Industrial Disputes Act.

12. In the present case it is clearly stated by the concerned workman that he was writing attendance and was maintaining the log book. The attendance register has not been filed to show that it was maintained by somebody else. The management has however given evidence to the effect that the attendance was written by one Sri Bharat Pandey, but Bharat Pandey was not been examined.

13. The management has no doubt examined three witnesses one of whom MW-1 is a clerk and MW-2 is the Senior Personnel Officer. MW-1 has stated in para 8 of his cross-examination that the concerned workman was in clerical Grade II, MW-2 the Sr. Personnel Officer has also admitted in para 6 of his cross-examination that the concerned workman was in clerical Grade II. Thus it is admitted that the concerned workman was in clerical Grade II. Though the two management witnesses have stated in their evidence that the concerned workman was doing supervisory duty only but the duty chart has not been filed to show that the main duty of the concerned workman was supervisory only. It may just be possible that some supervision work was done by the concerned workman but the evidence also the grade of the concerned workman clearly indicate that he was in clerical Grade II and was doing clerical job. In that view of the matter it must be held that the concerned workman is a workman within the meaning of Industrial Disputes Act and this Tribunal has got jurisdiction to decide the Reference.

14. The next issue is as to whether the action of the management in striking off the name of the concerned workman is legal or not. Ext.M-1 is a letter dated 16-7-76 purported to have been sent by the management to the concerned workman. It is mentioned in the letter that it was reported that the concerned workman was absenting from duty with effect from 15-6-76 without any information and permission and hence he was directed to join his duty within 48 hours from the receipt of this letter. The receipt of this letter has been denied. The peon book or postal receipt has not been filed to show that this letter was in fact despatched or received by the concerned workman. Ext.M-2 is the main letter dated 16-10-76 striking off the name of the concerned workman. It reads as follows:

"It has been found that you are absenting from duty without any information and permission from the management from 15-6-76 which amounts to misconduct violating the clause No. 27(16) of the Certified Standing Orders.

It is further reported that you have got employment in some other company without resigning from Bhowara Colliery, it is again a misconduct violating Coal Mines Regulation.

Since you have voluntarily abandoned your job, your name is hereby struck off from Bhowara Colliery. You may collect your final dues, if any, from the cashier on any working day after the vacating company's quarter and handing over the charge of Company's materials."

According to the management this letter originally was sent by peon book and ultimately by registered post vide receipt Ext. M-3. The acknowledgment receipt is not on the record.

15. From a perusal of this letter it will appear that the absence of the concerned workman according to the management themselves amounted to misconduct. For Misconduct the proper courts for the management was to issue a chargesheet against the concerned workman and pass dismissal order after holding a proper enquiry, but this was not done. The letter provides that since the concerned workman had voluntarily abandoned his job, his name had been struck off from the colliery rolls. Thus it was a case of abandonment of job by the management though the allegation of misconduct is also mentioned therein.

16. The certified standing order of the management has been marked Ext. M-5. It is well settled that the standing orders contain the terms and conditions of service of a workman within a mine. This standing order nowhere provides that for absence for more than a specified period the name of a workman can be struck off from the rolls or that it can be treated as voluntarily abandoning the job.

17. It was however contended on behalf of the management that the certified standing order is not exhaustive and the management has got power to struck off the name of a workman if he voluntarily abandons his job. This contention of the management however does not appear to be plausible. In this regard reference may be made to a ruling reported in 1 S.C.L.J. page 6 (Buckingham & Carnatic Co. Ltd., and Venkatiah and another). It provides that it is true that under common law an inference that an employee has abandoned or relinquished service is not easily drawn unless from the length of absence and from other surrounding circumstances an inference to that effect can be legitimately drawn and it can be assumed that the employee intended to abandon service. Abandonment or relinquishment of service is always a question of intention, and, normally, such an intention cannot be attributed to an employee without adequate evidence in that behalf. But where parties agree upon the terms and conditions of service and they are included in certified Standing Orders the doctrines of common law of considerations of equity would not be relevant. It is then a matter of construing the relevant terms itself. Thus according to this ruling if the parties agree upon the terms and conditions of service and they are included in the certified standing orders, the doctrines of common law or consideration of equity would not be relevant. In this case the terms and conditions of service of the concerned workman was governed by the certified standing orders. The said order did not make any provision or provide any condition under which an employer can treat a workman to have voluntarily abandoned his service. The management has right to take action against the concerned workman only under the provisions of certified standing orders and in face of the said order the management could not have taken recourse to the common law of abandonment of service by the concerned workman. In the above view of the matter the action of striking off the name of concerned workman cannot be said to be legal and valid.

18. The order of the management is defective and illegal on other grounds also. It has been well settled by the ruling reported in 1977 Lab. I.C. page 1695 that striking off name of the workman from the rolls amounts to retrenchment and unless the provisions of Section 25F (a) & (b) which are mandatory provisions are complied with, the order of striking off the name is illegal and cannot be sustained. Ext. M-2 is the only letter informing the concerned workman about the striking off his name. This does not provide that the concerned workman was given one month's notice in writing intimating the reason of his retrenchment or he was paid one month's pay in lieu of the notice. The concerned workman was also not offered retrenchment compensation as provided under Clause (b) of Section 25F of the I.D. Act. Admittedly none of these two provisions were complied with by the management in this case and hence on this score also the order of the management is illegal and invalid. The management also

did not comply with the provisions of Section 25F of the I.D. Act which came into effect from 5-3-1976. The ruling reported in 1980 Lab. I.C. page 687 would also show that the word 'retrenchment' includes every kind of termination.

19. Thus considering the above rulings and evidence on the record, I hold that the action of the management in striking off the name of the concerned workman is illegal.

20. It may however be stated at this very stage that the management has taken the plea that the concerned workman had taken up employment at Govindpur in the company of one Arjun Agarwalla & Company. The present mine was also the property of Arjun Agarwalla prior to nationalisation. The concerned workman, however, denied that he had taken employment at Govindpur under Arjun Agarwalla. The management has examined MW-1 who has stated that from enquiry he learnt that the concerned workman was working at the coke oven in a private concern at Govindpur. MW-2 the Senior Personnel Officer has stated that he called the concerned workman one day in his office and on enquiry the concerned workman told him that he was not interested in his job as he was working in coke oven of Arjun Agarwalla at Govindpur. MW-3 is Sri S. K. Banerjee, Manager of Bhowra Colliery. He has also stated that he made personal enquiry from the workman who told him that he was getting more money at Govindpur, but neither MW-2 nor MW-3 who are senior officers of the management took any statement in writing from the concerned workman to the above effect. If the concerned workman had given such a reply then they should have taken his statement in writing which should have been authentic proof to the effect that the concerned workman was employed elsewhere. In written statement it is not specifically stated that the concerned workman was employed under Arjun Agarwalla at Govindpur. Thus the allegation of the management that the concerned workman was employed elsewhere is not proved satisfactorily. Further given if, it was proved this did not improve the management's case so as to hold the order of the management legal and valid.

21. Considering all the above evidence and law points on the subject, I hold that the action of the management in striking off the name of the concerned workman from the rolls of the colliery is illegal and unjustified.

22. The next question as to what relief the concerned workman is entitled. It will appear that though the concerned workman has given evidence to the effect that he applied for leave to the management when he fell ill but no proof has been filed in support of it. The copy of such application or representation if any has not been filed. The only document filed on behalf of the concerned workman is Ext. W-3 which is a representation dated 2-11-76 after the concerned workman had received the order striking off his name. Thus it will appear that the concerned workman did not move in the matter for so many years and started taking steps after a long delay. Now if the concerned workman himself made such a long delay to represent his case through the union or get the matter referred to within a reasonable time, he cannot take advantage of claiming his back wages. The present reference was made in the year 1980. According to the management for the first time they received some letter from Sri J. D. Lal, Advocate in the year 1978.

23. Under such circumstances, in my opinion the concerned workman is entitled to be reinstated but without any back wages.

24. I give my award accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012(9)/80-D.III(A)]

New Delhi, the 15th May, 1982

S.O. 1928.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 187 GI/82—6

reby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kandla Port Trust Kandla and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th May, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, BOMBAY.

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande,
Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/4 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kandla Port Trust, Kandla.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employers : Shri S. G. Borkar, Advocate

For the workmen : No appearance

INDUSTRY : Ports and Docks

STATE : Gujarat

Bombay, dated the 22nd April, 1982

AWARD

The present reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 relates to the dispute between Shri T. C. Lulla the employee and the management of Kandla Port Trust. The following issue has been sent for adjudication under Order No. L-37012/1/81-D. IV(A) dated 26-5-1981 by the Ministry of Labour :—

“Whether the management of Kandla Port Trust, Gandhidham were justified in imposing the penalty of reduction to the post of Senior Clerk from the post of Store Keeper on Shri T. C. Lulla with effect from 21st August, 1975 ? If not, to what relief is he entitled ?

2. In spite of issue of notice neither the Union nor the employee concerned has appeared or filed claim statement against which the management of Kandla Port Trust filed written statement contending that before the order of reduction to the post of Senior Clerk from the post of Store Keeper passed against Shri T. C. Lulla, there was a domestic enquiry held investigating into six charges levelled against him, out of which three charges namely charges I, II and IV were held established as a result of which the competent authority accepting the finding passed the relevant order of reversion. Charges I, II and IV were as follows :—

“Charge No. I : That the said Shri T. C. Lulla, while functioning as Store Keeper, had mala fide motives in accepting a less quantity than that acknowledged material as per particulars given in the attached statement of allegations.

Charge No. II : That while functioning in the aforesaid office, the said Shri T. C. Lulla misbehaved with Assistant Engineer (S&I) on 16-8-1974 and displayed insubordination as brought out in the attached statement of allegations.

Charge No. IV : That while functioning in the aforesaid office, the said Shri T. C. Lulla wilfully allowed the contractor to take away one M. S. Plate which did not form part of the auctioned material along with the material auctioned.”

3. Having regard to the charges levelled against the employee and having regard to the fact, it was only after holding a domestic enquiry and after considering the report of the investigating officer, that the relevant order came to be passed and further, having regard to the fact that on behalf of the employee or Union there is no material placed as to why the Investigating Officer's report could not be acted upon basing on whose conclusions the competent authority passed the order against the employee concerned, it calls for no interference since it was fully justified, therefore no relief is in any way permissible. The finding therefore on the point of in controversy would be that the order was justified and therefore the employee is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-37012/1/81-D-IV(A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1982

का०आ० 1929.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०, बेलमपल्ली डिवीजन-1 के प्रबंधन से संबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजक और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करता वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी प्रसाद राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के प्रबंधन की स्वास्थ्य विभाग, बेलमपल्ली के सफाई मजदूर, श्रीमती गहन राजी को चिकित्सा बोर्ड को उसकी आयु के निर्धारण के लिए निर्दिष्ट किए बिना 1-9-81 से सेवा-निवृत्त करने की कार्यवाही स्यायोग्य है। यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[फाइल संख्या एच-21012(1) 82-डी IV(डी)]

एस० एस० मेहता, ईन्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1982

S.O. 1929.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Messrs Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division I and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes and Industrial Tribunal of

which Shri B. Prasada Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, is justified in retiring Smt Gaddam Raji, Sanitary Mazdoor, Health Department, Bellampalli with effect from 1-9-81 from service without referring for age assessment by Medical Board? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L-21012(1)/82-D-IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 मई, 1982

का०आ० 1930.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वाम मशीनरी कारपोरेशन, 34/1, मुरारी पुकुर रोड, कलकत्ता-67 जिसके अंतर्गत-160, नज़रुल इस्लाम एवेन्यू, कलकत्ता-54 स्थित उम्मा बिजनेस कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(34)/81-पी० एफ०-2]

New Delhi, the 12th May, 1982

S.O. 1930.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Das Machinery Corporation, 34/1, Murari Pukur Road, Calcutta-67, including its sales office at 160, Nazrul Islam Avenut, Calcutta-54, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S 35017/(34)/81-PF-II]

का०आ० 1931.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कला-दर्शन मरीन चैम्बर्स, पहली मरीन स्ट्रीट, न्यू मरीन, लाईन्स, मुम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/151/81-पी० एफ०-II]

S.O. 1931.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kala Darshan, Marine Chambers, 1st Marine Street, New Marine Lines, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35018(151)]81-PF-II]

का० आ० 1932.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यि टयूसडे बाजार, 207, रीगल इंडस्ट्रियल इस्टेट, ए० बी० मार्ग, सेबरी, मुम्बई-15, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/157/81-पी० एफ०-2]

S.O. 1932.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Tuesday Bazar, 207, Regal Industrial Estate, A.D. Marg, Sewree, Bombay-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establish;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(157)]81-PF-II]

का० आ० 1933.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी० सी० भाई फार्मास्यूटिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 304, अरुण चैम्बर्स जे० बादाजी रोड तारवेव मुम्बई-34 जिसके अन्तर्गत वापी स्थित उसकी शाखा और विकास एस्टेट, माफ भारे रोड, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई-63 स्थित उसका रजिस्ट्रकृत कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/158/81-पी० एफ० II]

S.O. 1933.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P.G.I. Pharmaceuticals (Private) Limited, 304, Arun Chambers, J. Dadajee Road, Tardeo, Bombay-34 including its branch at Vapi and Registered Office at Vikas Estate, Off. Aarey Road, Goregaon (East), Bombay-63, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establish;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(159)]81-PF-II]

का० आ० 1934.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केन्या एयर वेज, 199, चर्च गेट, रिक्लेमेशन, जमशेदजी टाटा रोड, बाम्बे-20 जिसके अन्तर्गत 12, के० बी० कमर्शियल सेण्टर बूसरी भजिल, वीनबाई टावर के पास लालवरबाजा, अहमद बाद स्थित उसका शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/160/81-पी० एफ०-2]

S.O. 1934.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kenya Airways, 199, Churchgate Reclamation, Jamshedji Tata Road, Bombay-20 including its branch at 12, K.B. Commercial Centre, 2nd Floor, Near Dinbal Tower, Laldarwaja, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(160)]81-PF-II]

का० आ० 1935.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोल्ड बायोमेडिक्स, 101ए, मिटल इस्टेट-4, सर एम०वी० रोड, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई-59 इसके कारखाने सहित, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/161/81-पी० एफ०-2]

S.O. 1935.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Golden Biomedics, 101 A, Mittal Estate No. 4, Sir M.V. Road, Andheri (East), Bombay-59, including its factory, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establish;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(161)]81-PF-II]

का०आ० 1936—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केमेटेक इण्डस्ट्रीज, प्रिन्ट सं० 17,44 और 45, सर्वोदय इण्डस्ट्रियल इस्टेट महाकाली कोस रोड, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-93 जिसके अन्तर्गत 88 बी, जोली मेकर चैम्बर्स-11-225, नरीमन पार्क, मुम्बई-21 स्थित उसका कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/162/81/पी०/एफ-2]

S.O. 1936.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chematech Industries, Unit No. 17, 44 and 45, Sarvodaya Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri East, Bombay-93 including its Office at 88-B, Jolly Maker Chambers-II, 225, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(162)]81-PF-III

का०आ० 1937—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चेट्टियार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जी० 4 व्यासरपाडी इंडस्ट्रियल इस्टेट मद्रास-399 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/164/81/पी०/एफ० 1]

S.O. 1937.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chettiar Industrial Corporation, C-4, Vyasarpadi Industrial Estate, Madras-39, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S.35019(164)]82-PF.III

का०आ० 1938—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीकाकुलम कन्सुमर्स कोऑपरेटिव सेन्ट्रल स्टोर्स लिमिटेड, सं० ए-709, श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/365/81-पी०/एफ०-2]

S.O. 1938.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Sriakulam Consumers Co-operative Central Stores Limited, No. A-709, Sriakulam, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(365)]81-PF.III

का०आ० 1939—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सदर्न नाइट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, सं० 86, अथिपेट, मद्रास-58 जिसके अन्तर्गत 3/202 गोविन्दप्पा नायक स्ट्रीट, मद्रास : स्थित उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/382/81-पी०/एफ-2]

S.O. 1939.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Southern Nitrochemicals Limited, No. 86, Athipet, Madras-58 including its Registered Office at 3/202, Govindappa Naick Street, Madras-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(382)]81-PF.III

का०आ० 1940—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उडिपी शान्ति बिहार, 469, टी०एच० रोड, मद्रास-21, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/398/81-पी०/एफ०-2]

S.O. 1940.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Udiipi Shanthi Vihar, 469, T.H. Road, Madras-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (1) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(398)|81-PF-II]

का०आ० 1941—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सोना रबबर (प्राइवेट) लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एट्टमानूर, कोट्टयम जिला केरल, जिसके अन्तर्गत जवाहिरा बिल्डिंग कोर्टयम, केरल स्थित उसका प्रशासनिक कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एम-35019(399)/81-पी०एफ०-2]

S.O. 1941.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sona Rubber (Private) Limited, Industrial Estate, Ettimanoor, Kottayam District, Kerala, including its Administrative Office at Zachariah Building, Kottayam, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (1) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(399)/81-PF-II]

का०आ० 1942—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी० कुठलमम्मल पावरलूम फैक्ट्री, 120 रेलवे फीडर रोड, संकरन कोट्टल, 627756, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस-35019(400) 81-पी०एफ०-2]

S.O. 1942.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs V. Kuthalam Powerloom Factory, 120, Railway Feeder Road, Sankarankoil-627756, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (1) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(400)/81-PF-II]

का०आ० 1943—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बालकृष्ण टाकीज नं० 665 थिरुवोट्टियूर हार्ड रोड, मद्रास-19 नामक

स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एम-35019(401) 81-पी०एफ०-1]

S.O. 1943.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Balakrishna Talkies No 665, Thiruvottiyur High Road, Madras-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (1) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(401)/81-PF-II]

का०आ० 1944—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाला सुश्रामण्म रोडवेज 4 त्रिची रोड, डिन्दिगुल-7, मद्रुरै जिला, तमिलनाडु, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एम०-35019(402) 81-पी०एफ०-2]

S.O. 1944.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Balasubramaniam Roadways, 4 Trichy Road, Dindigul-7, Madurai District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (1) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(402)/81-PF-II]

का०आ० 1945—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीम गंगे विनायकराव चट फण्ड्स मूर सॉफ्ट, मद्रास-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एम०-35019(403) 81-पी०एफ०-2]

S.O. 1945.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees

In relation to the establishment known as Messrs Om Gangai Vinayagar Chit Funds, Moore Market, Madras-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S. 35019(403)/81-PF-II]

का०आ० 1946.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मागमान इन्टरप्राइजिज 52, धार०के० नगर, वलसरवाक्कम, मद्रास-81 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/404/81-पी०एफ०-2]

S.O. 1946.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nagman Enterprises, 52, R. K. Nagar, Valasaravakkam, Madras-81, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establish;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(404)/81-PF-II]

का०आ० 1947.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रॉयल थियेटर डाकबर चिन्नालापट्टी, अंबापुराई (एम०आर०धार्ड०), जिला मदुराई, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[सं० एस०-35019/406/81-पी०एफ०-2]

S.O. 1947.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees' in relation to the establishment known as Messrs Royal Theatre, Chinnalapatti Post, Ambuthurai (SRY), Madurai District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(406)/81-PF-II]

का०आ० 1948.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडियन शिपिंग एजेंसीज (प्राइवेट) लिमिटेड कोडिबैजल बेन, मंगलूर त्रिसके अन्तर्गत 9/2 रिचमन्ड रोड, बंगलूर स्थित उसका मुख्य कार्यालय भी है। नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/408/81-पी०एफ०-2]

S.O. 1948.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indian Shipping Agencies (Private) Limited, Kodiabail, Mangalore, including its Head Office at 9/2, Richmond Road, Bangalore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establish;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(409)/81-PF-II]

का०आ० 1949.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रेसीडेंसी शू कंपनी, 29, पराम्बूर हाई रोड, मद्रास-12 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/416/81-पी०एफ०-2]

S.O. 1949.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Presidency Shoe Company, 29, Perambur High Road, Madras-12, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(416)/81-PF-II]

का०आ० 1950.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी० आर० एन० बिस्मिथ (मनाहम लि० के पास) 20-24, बराडिकुडार्ई स्ट्रीट, मिकी-2 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35019/419/81-पी०एफ-2]

S.O. 1950.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P.R.N. Buildings (Near Malaivasal) 20-24, Theradikadal Street, Trichy-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(419)|81-PF-II]

का० आ० 1951.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्राफो-एहाम, 28, कूम्बलामन कोईल स्ट्रीट, मद्रास-81 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35019/420/81-पी०एफ-2]

S.O. 1951.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Graphoids, 28, Kumbalamman Koi! Street, Madras-81, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(420)|81-PF-II]

का० आ० 1952.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सी० एल० आर० एम० 139/4, महात्मा गांधी रोड शास्त्री नगर, तिरुवन्मियूर, मद्रास-41, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35019/421/81-पी०एफ-2]

S.O. 1952.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs

B. L. R. S. 139/4, Mahatma Gandhi Road, Sastri Nagar, Thiruvannmiyur, Madras 41, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(421)|81-PF-II]

का० आ० 1953.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 11-5-401/1, रॉड हिल्स, हैदराबाद-4 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35019/424/81-पी०एफ-2]

S.O. 1953.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Andhra Pradesh State Police Housing Corporation Limited, 11-5-041/1, Red Hills, Hyderabad-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(424)|81-PF-II]

का० आ० 1954.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वुड क्राफ्ट्स, 1-2-524, डोमागुडा, हैदराबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35019/425/81-पी०एफ-2]

ए० के० भट्टारार्, अवर सचिव

S.O. 1954.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Wool Crafts, 1-2-524, Domaiguda, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (i) of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(425)|81-PF-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

